

संपादकीय

कानून से ऊपर

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। अक्टूबर से नौ नोटिसों से बचने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें दिल्ली शराब नीति मामले में गुरुवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया। इस घटनाक्रम के साथ, केजरीवाल इस मामले में गिरफ्तार होने वाले आम आदमी पार्टी (आप) के तीसरे वरिष्ठ नेता बन गए हैं। केजरीवाल और उनकी पार्टी, आप ने कहा है कि वह सलाखों के पीछे से भी शासन करना जारी रखेंगे, लेकिन कानून क्या कहता है? खैर, यह एक ऐसी चीज है जिस पर अदालतों को गौर करने की जरूरत है कि क्या एक मुख्यमंत्री जो किसी मामले में आरोपों का सामना कर रहा है, वह जेल से राज्य सरकार चला सकता है। यह एक अभूतपूर्व और सबसे अव्यवहारिक विचार है, भले ही यह भावनात्मक रूप से आवेशित स्थिति में दिया गया बयान हो। झारखण्ड के मुख्यमंत्री, जो भी आरोपों का सामना कर रहे हैं, ने ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने से कुछ मिनट पहले इस्तीफा दे दिया था। अब, ये सभी मुद्दे एक बुनियादी सवाल उठाते हैं क्या कानून निर्माता कानून से ऊपर हैं? कानून के शासन का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, यहां तक कि सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी भी। फरवरी 2018 में एक मामले में मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ ने पुलिस को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए दो नगरसेवकों – भाजपा के परशुराम म्हात्रे और शिवसेना की अनीता पाटिल – पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। ~~प्रीति~~ तो ~~प्रीति~~ से ~~प्रीति~~ हैं। तो ~~प्रीति~~ हैं,

दिया। राजनातक नता कानून से ऊपर नहा ह। व मंगवान नहा ह, या ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो कानूनों का उल्लंघन करने के अधिकार का दावा कर सकें, “न्यायाधीशों ने कहा। लेकिन, दिल्ली शराब घोटाले में हमने देखा है कि कैसे बीआरएस एमएलसी के कविता इस आधार पर ईडी के सामने पेश होने से बच रही थीं कि एक विधायक के रूप में वह ईडी द्वारा दी गई विशेष तारीख पर उपलब्ध नहीं थीं और इसलिए उनके सामने पेश नहीं हो सकतीं। वह इस मामले में शीर्ष अदालत भी गई थीं। केजरीवाल भी मुख्यमंत्री के तौर पर कई कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण ईडी के सामने पेश नहीं हुए। मैं शराब घोटाले के गुण-दोष या मनी लॉन्ड्रिंग में कौन शामिल है या इसमें कितनी राशि शामिल है, इस पर नहीं जा रहा हूं। बुनियादी सवाल यह है कि क्या एक आम आदमी को जांच एजेंसियों, चाहे वह ईडी हो या सिफ्र क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन, से नोटिस न लेने का समान विशेषाधिकार मिल सकता है। केजरीवाल और कविता ने कहा कि वे अपनी आधिकारिक क्षमताओं में व्यस्त हैं। आम आदमी भी, जो कहीं न कहीं काम कर रहा है, अपने पेशे या अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों के मामले में कम महत्वपूर्ण नहीं है। क्या उन्हें कानून लागू करने वाली एजेंसियों से कानून निर्माताओं को मिलने वाला शिष्टाचार मिलेगा? उसे पुलिस वाहन में बिठाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा और यहां तक कि उसे थर्ड डिग्री का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब राजनेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, तो सभी रंग और आकार के राजनेताओं को एक छतरी के नीचे एकजुट होते और केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए देखना निराशाजनक है। मैं यह कहकर किसी को भी कलीन चिट नहीं दे रहा हूं कि इसमें कोई राजनीति शामिल नहीं है या यह राजनीति से प्रेरित कदम है या ऐसा ही कुछ है। लेकिन मुझे आश्चर्य

इस बात पर है कि गिरफ्तारी के बाद, गुरुवार को राजनीतिक परिवृश्य में विभिन्न पंख वाले पक्षी संसद की सर्वोच्चता के क्षण के मुद्दे पर एक साथ बात करने लगे, कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जैसा कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है। कहा। ये सभी नेता यह स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में सब कुछ ठीक नहीं है। सच तो यह है कि राजनीतिक दलों में कुछ भी ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी को शुरा हुआ तानाशाह और बीजेपी को शैतानी शक्ति जो एक मृत लोकतंत्र बनाना चाहती है करार दिया। मीडिया समेत तमाम संस्थाओं पर कब्जा करना, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से पैसा वसूलना और मुख्य विपक्षी दल के खाते फ्रीज करना ही शैतानी ताकतश के लिए काफी नहीं है, अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। एक सामान्य बात। भारत इसका करारा जवाब देगा, शुगांधी ने एक्स (पूर्व में टिवटर) पर पोस्ट किया। लेकिन राहुल को इस बात का जवाब देने की जरूरत है कि पर्युचर गमिंग, मेघा इंजीनियरिंग, विवक सप्लाई चेन, वेदांता, जिंदल स्टील, केवेंटर फूड पार्क और उन कंपनियों की लंबी सूची से बांड के रूप में प्राप्त धन के बारे में क्या है जो एसबीआई ने शीर्ष अदालत को सौंपी है। सत्तारूढ़ दल होने के नाते स्वाभाविक रूप से भाजपा को विपक्ष की तुलना में अधिक पैसा मिला होगा। यदि भाजपा को बांड के माध्यम से धन प्राप्त करना जबरन वसूली है तो कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल को बांड के माध्यम से धन प्राप्त करना क्या है? हर राजनीतिक दल को केक का अपना हिस्सा मिला। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आप नेता की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए कहा कि यह गिरफ्तारी विपक्षी आवाजों को चुप कराने का एक हिस्सा है। "दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से वीभत्स और पक्षपातपूर्ण है।

वैश्विक मंथन आगे – पुतिन की जीत के बाद और भी चुनाव होने की संभावना

विनो

A formal portrait of Russian President Vladimir Putin. He is seated at a dark wooden desk, looking slightly to his left with a serious expression. He is wearing a dark blue suit jacket over a white shirt and a dark red tie. Behind him is a large Russian flag with its characteristic blue, white, and red horizontal stripes. The setting appears to be an official government office.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 17 मार्च को 87 प्रतिशत वोट के साथ अपने देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता। 2000 में पहली बार सत्ता संभालने के बाद से यह उनका पांचवां कार्यकाल होगा। छह साल का कार्यकाल उन्हें 2030 तक ले जाएगा, जिससे वह सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले बन जाएंगे। जोसेफ स्टालिन को छोड़कर, रूस में या तत्कालीन सोवियत संघ में सरकार के प्रमुख। बीबीसी ने बताया कि रूस के स्वतंत्र निगरानीकर्ता गोलोस को चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने से रोक दिया गया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने प्रतिद्वंद्वियों को जेल भेजने के कारण इसकी समझौतावादी प्रकृति की ओर इशारा किया। 16 फरवरी को जेल में प्रमुख असंतुष्ट एलेक्सी नवलनी की रहस्यमय मौत ने निर्णायक रूप से जीतने के लिए यह अन्वर्तन के दूर संकल्प को खोया।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होंगे। इन सभी चुनावों के नतीजे वैशिक शक्ति समीकरणों पर अलग-अलग स्तर के प्रभाव डाल सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। श्री पुतिन की जीत पर विभाजित प्रतिक्रिया अत्यधिक धूलीकृत दुनिया में मौजूदा शक्ति संरेखण को दर्शाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश यूरोप ने इसे तुरंत अलोकतांत्रिक और अनुचित करार दिया। ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड कैमरन ने कहा कि यह घटना की गहराई को दर्शाता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने प्रतिद्वंद्वियों को जेल भेजने के कारण इसकी समझौतावादी प्रकृति की ओर इशारा किया। 16 फरवरी को जेल में प्रमुख असंतुष्ट एलेक्सी नवलनी की रहस्यमय मौत ने निर्णायक रूप से जीतने के लिए यह अन्वर्तन के दूर संकल्प को खोया।

कम्युनिस्ट प्रतिद्वंद्वी को केवल चार प्रतिशत वोट मिले। जब पश्चिमी देशों की इस आलोचना को अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया के साथ जोड़ा जाता है तो भूराजनीतिक दोष रेखाएँ उभरती हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिन्होंने 2022 में यूक्रेन युद्ध से पहले श्री पुतिन के साथ ष्टोई सीमा नहीं साझेदारी की घोषणा की थी, ने कहा कि श्री पुतिन की जीत अशांत दुनिया में निश्चितता लाती है। श्री पुतिन ने 18 मार्च को अपने रेड स्क्वायर भाषण में, एक-चीन सिद्धांत को मजबूत समर्थन दिया और घोषणा की कि स्ताइवान पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक अंतर्राष्ट्रीय हिस्सा है। यह सार्वजनिक प्रेम उत्सव इन दो शक्तियों द्वारा साझा की गई दारणा को दर्शाता है कि अमेरिकी आधिकार्य घट रहा है। आमतौर पर

लोग या तो तटस्थ हैं या रूस की ओर झुक रहे हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) बताती है कि विस्तार-पूर्व पांच सदस्यीय ब्रिक्स के सदस्य ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और भारत भी इसी मुद्दे पर पक्ष चुनने से बचते हैं। इसलिए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन को बधाई देने वाले पहले नेताओं में से थे। श्री मोदी ने रूस के साथ भारत के संबंधों को बढ़ानी तक आयाम के साथ समय-प्रारक्षणित, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त बताया। भारी छूट वाला रूसी तेल वैशिक अनिश्चितता के समय भारतीय रिफाइनरों के लिए एक वरदान के रूप में आया, जो पारंपरिक रूप से तेल की कीमतों को बढ़ाता है। यूक्रेनी निर्यात को बाधित करने के बाद, रूस ने अनाज के विर्गन पाए भी आपाती तंग से आनन्द लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन युद्ध जारी रखना के दूर संकल्प को खोया,

वैशिक कमी और मूल्य वृद्धि से बुरी तरह प्रभावित कई अफ्रीकी देशों को मुफ्त अनाज देने का वादा किया। इनमें सोमालिया, माली, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जिम्बाब्वे आदि शामिल हैं। इसने रूस को यूक्रेन पर फरवरी 2022 के हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र में प्रारंभिक रूसी विरोधी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम बनाया है, जब हमले की निर्दा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव ने हमले की निंदा की थी। 141 देशों का समर्थन। राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी रेड स्क्वायर रैली में सीना ठोक दिया। यूक्रेन के 2023 शरदकालीन आक्रमण को उलटने के बाद, उसने मनोवैज्ञानिक रूप से विभाजित यूरोप पर हमला करने का फैसला किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन युद्ध जारी रखना के दूर संकल्प को खोया,

उन्होंने एक साथ शांतिपूर्ण और पड़ेसी संबंधों की मांग की, जो इस प्रावधान के अधीन था कि यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने यूक्रेनी क्षेत्र पर एक सुरक्षा क्षेत्र का प्रस्ताव रखा। इसमें यूक्रेन को निरस्त्र करने और इसे एक असहाय बफर जोन के रूप में प्रस्तुत करने की इच्छा निहित है, जिसे रूस और पश्चिम स्वीकार कर सकते हैं। श्री पुतिन की चालाकी कई धारणाओं पर आधारित है। एक, जून के चुनावों के बाद अगर दक्षिणपंथी कहूरपंथी यूरोपीय संसद पर कब्जा कर लेते हैं या उसे पर्याप्त रूप से प्रभावित करते हैं, तो यूक्रेन की सहायता करने पर यूरोप की सहमति और अधिक टूट सकती है। दूसरा, श्री पुतिन नवंबर के अमेरिकी चुनावों पर दांव लगा रहे हैं, जिससे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की आवायाशित जीत तोड़ी

इजराइल की रेत में उलझाना चाहेगा। यदि श्री ट्रम्प जीतते हैं, तो गाजा की स्थिति खराब होने की संभावना है क्योंकि वह स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति जो बिडेन की तुलना में इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायल के प्रति अधिक पक्षपाती हैं। वहाँ एक विरोधाभास रहता है। जबकि श्री ट्रम्प द्वारा यूक्रेन को रूस के साथ समझौता करने का आग्रह करने की संभावना है।

स्पेक्ट्रम पर रहने वाले लोगों के लिए एक देखभाल करने वाला हाथ

लालित
मेरी दूसरी पोती का जन्म 2007 हुआ था। वह एक खुशमिजाजी थी और पहले कुछ महीनों में घंटों निरर्थक बड़बड़ती और लाले हंसती रहती थी। वह सामान्य से बढ़ी, कुछ शब्द और फिर ऐ वाक्य बोलने लगी। लेकिन द ही, जब वह लगभग डेढ़ वर्ष की थी, तब उसे ऑटिज्म हो गया। सौभाग्य से, मेरी बेटी ने कार की स्थिति में नहीं रहने का लाला किया। उसने चिकित्सीय प्रयत्न मांगी और बेहद धीमी गति उपचार शुरू हुआ। सोलह साल उम्र में, वह अभी भी ऑटिस्टिक जैसा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले आमतौर पर करते हैं — जैसा उत्कृष्ट धारावाहिक, द गुड लैंटर में डॉ. शॉन मर्फी के मामले हुआ था — लेकिन मेरी बेटी उसका परिवार अब इससे बचने में बेहतर सक्षम हैं। दुखद बाई यह है कि ऑटिज्म कम के बजाय बढ़ रहा है। दो वर्ष के पहले, यह अनुमान लगाया था कि अमेरिका में यह प्रत्येक व्यक्तियों में से एक थाय अब, रोग नियत्रण और रोकथाम कदम का अनुमान है कि यह 36 में से एक है। इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में प्रकाशित 2021 के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में यह घटना 68 में से एक है। 2017 में हिमाचल प्रदेश में एस के रैना के नेतृत्व में एक सर्वेक्षण में राज्य के तीन जिलों के ग्रामीण, आदिवासी और शहरी क्षेत्रों में ऑटिज्म की 0.15 प्रतिशत घटनाओं का चौकाने वाला आंकड़ा सामने आया। अगर हम अखिल भारतीय औसत भी लें, तो भी भारत में 20 मिलियन लोग ऑटिज्म से पीड़ित हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है। ऑटिज्म के मामलों में लड़का—लड़की का अनुपात भारत में 3रु 1 और अमेरिका में 4रु 1 है। 2018 में लैंसेट पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित एक पेपर में, जो ओवुसान्या वी ओ और अन्य द्वारा लिखा गया था, यह कहा गया है कि न्यूरोडेवलपमेंटल समस्याओं वाले 95 प्रतिशत लोग मध्यम और निम्न आय वाले देशों में हैं। भारत के आंकड़े शायद कम बताए गए हैं क्योंकि वहां जागरूकता की कमी है। यहां तक कि शिक्षित और संपन्न लोग भी अपनी सतानों के सामने आने वाली न्यूरोडेवलपमेंटल समस्या के बारे में इनकार की स्थिति में रहना पसंद करते हैं, जिससे शुरुआती चरणों में सुधार की संभावना कम हो जाती है। जैसे ही हम 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस के करीब पहुंच रहे हैं, हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि एक समाज के रूप में हम सामूहिक रूप से क्या कर सकते हैं। माता-पिता और देखभाल करने वालों द्वारा समस्या को स्वीकार करना इसे यथासंभव हद तक संबोधित करने की दिशा में पहला कदम है। यह जितनी जल्दी होगा, इसे कम करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। पिछले साल विश्व ऑटिज्म दिवस पर, संयुक्त राष्ट्र ने कहा, “हम ऑटिस्टिक लोगों को ठीक करने या परिवर्तित करने की कथा से दूर जा रहे हैं और इसके बजाय ऑटिस्टिक लोगों को स्वीकार करने, समर्थन करने और शामिल करने और उनके अधिकारों की वकालत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह सभी ऑटिस्टिक लोगों, उनके सहयोगियों, व्यापक मानकों को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य कार्यबल की क्षमता को मजबूत करने में योगदान देने की भी प्रयास करता है। यह ऑटिज्म और अन्य विकासात्मक विकलांगताओं वाले लोगों के लिए समावेशी और सक्षम वातावरण को बढ़ावा देता है और देखभाल करने वालों को सहायता प्रदान करता है। भारत में समस्या का पैमाना बहुत बड़ा है। कानूनी तौर पर प्रावधान अस्तित्व में हैं। सविधान में सर्वव्यापी अनुच्छेद 41 में लिखा हैरू ब्याज्य, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी के मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। विकलांगता, और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में। ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए सरकारों की प्रतिबद्धता बढ़ाने पर केंद्रित हैं। यह ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के लिए उचित और प्रभावी देखभाल प्रदान करने और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 मानसिक रूप से है।

युनावी बांड के पचास रंग

आसफ मुझे लगा कि चुनावी बांड को समझने के लिए मेरे पास एक और अंग्रेजी प्रेरणा है – 1939 में विस्टन चर्चिल के प्रसिद्ध रेडियो भाषण से, जब उन्होंने रूस को एक पहेली के अंदर, एक रहस्य में लिपटी एक पहेली के रूप में वर्णित किया था। मैं अंग्रेजी भाषा की बारिकियों के साथ चुनावी बांड पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं जिसमें किसी स्थिति का वर्णन करने के लिए तीन अलग-अलग शब्द हैं जो आपस में जुड़े हो सकते हैं रूस गोपनीयता, गोपनीयता और गुमनामी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी बताती है कि गोपनीयता का अर्थ है शनिजी जानकारी को गुप्त रखा जानाश। दूसरी ओर, गोपनीयता वह है जहां जानकारी का एक टुकड़ा केवल एक व्यक्ति या कुछ लोगों को पता होता है और इसे दूसरों को नहीं बताया जाना चाहिए। गुमनामी से तात्पर्य उस स्थिति से है कि जाटल सबधा का नाम नहीं दिया जाता या जाना नहीं जाता। अब, कुख्यात बॉन्ड को समझने के लिए उस सबको जूसर-ब्लैंडर में डालें। जिन कंपनियों ने उन्हें खरीदा, वे अनुचित रूप से उल्लंघन महसूस कर रही हैं, जबकि मीडिया और पार्टी से बाहर रह गई राजनीतिक संस्थाएं उन नामों को खुशी-खुशी सामने ला रही हैं, जिन्हें अब तक वोल्डमॉर्ट जैसी स्थिति का आनंद मिला हुआ था और उनका नाम उजागर नहीं किया गया था। हमें यह विश्वास दिलाया गया कि बांड खरीदने वाले पक्षों और उसके एकाधिकार जारीकर्ता एसबीआई के बीच जो हुआ, वह गोपनीयता का मामला था जो गोपनीयता के साथ निष्पादित होने पर आम जनता के लिए गुमनामी सुनिश्चित करेगा। लेकिन राज्य के पास एसबीआई का स्वामित्व होने और साझा करने वाले गुमनामी का बांड के रूप में बाणित किया जा सकता है, लेकिन प्रभावी रूप से कुछ चुने हुए लोगों की गोपनीयता को शामिल करने वाला एक अंदरूनी काम था। यह तब और अधिक जटिल हो जाता है जब आपको पता चलता है कि विपक्षी दलों को भी बांड प्राप्त हुए हैं, लेकिन (इसमें कोई आश्चर्य नहीं) ज्यादातर प्रांतीय सरकारों में सत्ता में हैं। फिर आप ध्यान दें कि कुछ कंपनियाँ जिन्होंने दर्जनों या सैकड़ों करोड़ रुपये के बांड खरीदे थे, वे साझेदारी, निदेशक या अधिकारी को उन लोगों को चुनौती देने वाले एक प्रकार के जादूगर के रूप में देख सकते हैं जिनका नाम नहीं लिया जाएगा। जिन आलोचकों को लगता है कि व्यवस्था में उनके भरोसे को लोकतंत्र ने धोखा दिया है, जिसने सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता को निजी मामलों में गोपनीयता से ऊपर रखा है, वे स्वाभाविक रूप से परेशान हैं।

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

हित समूह और लोकतंत्र



आदित्य

गणेश मांझी द्वारा चुनावी बांड पर न के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले नहें जर विवड प्रो क्यो (क्यूपीक्यू) ऐसी चीज नहीं है जिस पर चर्चा हो रही है। यह लगभग उत्तर जितना ही पुराना है। साहित्य एक बड़ा समूह है जिसने हासिक रूप से फर्क के सिद्धांत प्रकाश डाला है। अर्थात् हित समूह लॉबी चुनाव से पहले किसी नेता या राजनीतिक दल के चुनावी यान को वित्तपोषित कर सकते हैं प्रकार के नियामक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चरम मामलों में, इस फर्क के परिणामस्वरूप कुछ हाथों में धन का संकेंद्रण हो सकता है और जनता को नुकसान हो सकता है, जिससे देश में उच्च असमानता हो सकती है। उदाहरण के लिए, बाउटन एट अल (2013, 2014) और गॉस (2010) ने अमेरिका में शक्तिशाली बंदूक लॉबी के बारे में बताया जो चुनावों के दौरान राजनेताओं / राजनीतिक दलों को अर्थिक रूप से मदद करते हैं, यही

कारण है कि उस देश में बंदूकों की खुली खरीद को भी नहीं रोका जा सका। काफी देर तक इतनी हलचल के बाद, ह्यूबर और किर्चलर (2013) ने उन कंपनियों के शेर्यों पर उच्च रिटर्न की रिपोर्ट दी है, जिन्होंने 1992 से 2004 के दौरान चुनाव खर्च में सबसे अधिक योगदान दिया था। प्राचीन चारा हित समूहों और राजनीतिक दलोंधाजनेताओं के बीच क्यूपीक्यू संबंध का पता लगभग 60 ईसा पूर्व से 53 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य में लगाया जा सकता है, जब जूलियस सीजर सत्ता (रोमन साम्राज्य में गॉल के वाणिज्य दूत) का लक्ष्य बना रहा था और उसने मार्कस से वित्तीय मदद ली थी। लिसिनियस क्रैसस (रोमन इतिहास का सबसे धनी व्यक्ति) और नियस पॉम्पी मैग्नस। तीनों – जूलियस सीजर, क्रैसस और पॉम्पी – ने एक समूह बनाया जो श्रायमविरेट्स के नाम से प्रसिद्ध है, और उन्होंने कई वर्षों तक रोमन साम्राज्य पर शासन किया। क्रैसस को सामान्य रूप से विश्व इतिहास के और विशेष रूप से रोमन साम्राज्य के सबसे धनी लोगों में से एक माना जाता है। बदले में, प्लूटार्क के अनुसार, क्रैसस और पॉम्पी दोनों को कर छूट और भूमि अनुदान मिला। विशेष रूप से, क्रैसस ने बहुत सारी संपत्ति और शक्ति जमा की, 7,100 प्रतिभाओं की एक बड़ी राशि, उसके पास व्यापक रियल एस्टेट हित थे और उसके पास चांदी की खदानें थीं। उसके पास बड़ी संख्या में दास थे और उसके पास इतनी बड़ी संपत्ति थी कि वह अपनी सेना का खर्च उठासकता था। प्रतिदान आज, हित समूह लोकतंत्र का एक अविभाज्य हिस्सा बन गए हैं, और कई मायनों में, वे क्यूपीक्यू (माझी और मेहराज, 2018) के लिए अन्योन्याश्रित हैं। कपूर और वैष्णव (2011) ने यह भी पाया कि राजनेता और बिल्डर एक फक्च में संलग्न होते हैं, जिसके तहत पूर्व अपनी अवैध संपत्ति दूसरे के पास रखते हैं, और बाद वाले

चुनाव के दौरान धन की अनुकूल डिलीवरी के लिए पूर्व पर भरोसा करते हैं। दिखाने के लिए, वे रियल एस्टेट बाजार के राजनीतिक संबंध का अध्ययन करते हैं और पाते हैं कि चुनाव के दौरान यह बाजार नीचे चला जाता है, ठीक इसलिए क्योंकि राजनेता रियल एस्टेट से अपनी अवैध संपत्ति निकाल लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए सरकार द्वारा आवंटित बजटीय व्यय के अलावा चुनाव लड़ने वाले एजेंट के लिए चुनाव व्यय का वित्तपोषण करते हैं। हालाँकि, भारतीय चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र अभी भी पूँजीपति वर्ग और शक्तिशाली व्यापारिक घरानों के चंगुल में है, जिस पर एक समय डॉ. बीआर अंबेडकर को संदेह था। अम्बेडकर ने गांधीवादी ग्राम स्वराज के विचार को खारिज कर दिया और कहा कि ग्रामीण भारत सामंती तत्वों और उच्च जातियों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और परिणामस्वरूप निचली जाति और अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिलेगा। हालाँकि, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के संदर्भ में ग्राम स्वराज के गांधीवादी विचार को संविधान के अनुच्छेद 40 (1) में जगह दी गई थी, जिसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा। जैसा कि उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है (वेंकटसु, 2016)। राजनेताओं और कॉर्पोरेट रिश्तों के इस पूरे चक्र को रघुराम राजन (2017) ने अपनी पुस्तक आई ड्यूक्स्ट आई ड्यू में यह कहते हुए अच्छी तरह से संबोधित किया है रुग्रीबों और वचितों को नौकरी और सार्वजनिक सेवाएं प्राप्त करने में मदद करने के लिए राजनेताओं की आवश्यकता होती है।

पा। राष्ट्रपति पतिन के मर्यादा के लिए यह एक अद्वितीय घटना है।



साथ ही डेमोक्रेट अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों पर नियंत्रण खो देंगे। उनका अनुमान है कि इससे यूक्रेन को अमेरिकी समर्थन खट्टम हो जाएगा। तीसरा, गाजा युद्ध मध्य पूर्व को अस्थिर रखता है, जिससे अमेरिका-इजराइल मतभेद बिगड़ रहे हैं। इस बीच, अधिक कट्टर दक्षिणपंथी बहुमत ने ईरानी संसद पर कब्जा कर लिया है। इस प्रकार, ईरान- चीन-रूस अधिकारीया अमेरिका को अपने और

